

मछली मारने वाली नौकाओं का होगा पंजीकरण-सफवी

यात्रियों की आवाजाही पर लगेगी रोक

**कॉरपोरेट
सोसायटी पर भी
कसेगा शिकंजा**

कार्यालय संवाददाता @ कोलकाता

मछली मारने वाली नौकाओं पर यात्रियों की आवाजाही पर राज्य सरकार रोक लगाने जा रही है। मछली मारने वाली नौकाओं का पंजीकरण करने की भी बात चल रही है। राज्य के सहकारिता व जल परिवहन मंत्री हैदर अली सफवी ने बताया कि राज्य सरकार थल परिवहन सेवा की तरह जल परिवहन सेवा को भी बढ़ाना चाहती है। राज्य सरकार फेरी सेवाओं को पुनर्जीवित कर नए फेरी सेवाएं

शुरू करना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि कॉरपोरेट सोसायटी पर भी लगाम लगाने की योजना बना रहे हैं।

मंगलवार को मर्चेंट-चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित परिचर्चा में उन्होंने कहा कि हुगली जलपथ परिवहन समन्वय समिति भी काम नहीं होने के कारण बंद पड़ी है। इसे फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। राज्य में मछली मारने वाली नौकाओं का व्यावसायिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके विभाग के पास राज्य के मछली मारने वाली नौकाओं की संख्या की जानकारी नहीं है। इन नौकाओं पर यात्रियों की आवाजाही दुर्घटना को दावत दे सकती है। उन्होंने कहा कि इन नौकाओं का पंजीकरण



वक्तव्य रखते मंत्री हैदर अली सफवी, साथ में है चेम्बर अध्यक्ष एस. सोंथलिया।

किया जाएगा। इस पर भी निगरानी की जाएगी कि इन नौकाओं का इस्तेमाल यात्रियों की आवाजाही में इस्तेमाल ना हो। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने इनलैंड वाटर डायरेक्टोरेट को विभाग के रूप में गठन किया। इसलिए इस

विभाग को काम संभालने में थोड़ा समय लग रहा है। जल परिवहन विभाग जल्द ही इस पर शुरू किया जाएगा। बजट व योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने विभिन्न सोसायटी की

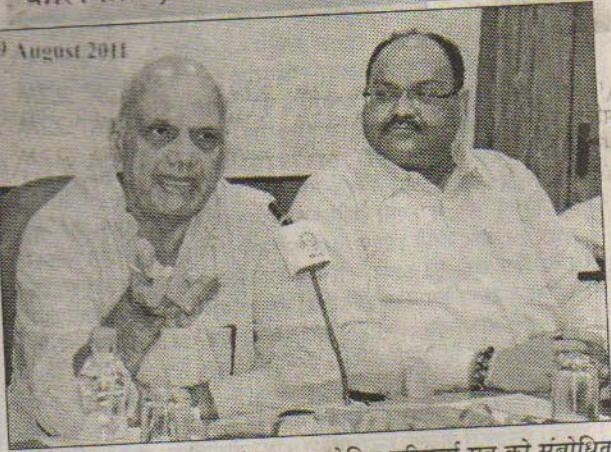
स्थिति पर कहा कि उनकी मंगलवार को सोसायटी के कामकाज की समीक्षा को लेकर एक बैठक हुई जिसमें विधायक, हावड़ा के डीएम, परिवहन विभाग के सचिव व विभिन्न सोसायटी के सचिव शामिल हुए। इस बैठक में सोसायटी के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। उन लोगों ने बताया कि उनके सामने भी बड़ी समस्या है। उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता। वे लोग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं।

उन्होंने बताया कि इस बैठक में साफ कर दिया गया कि सोसायटी के कामकाज की समीक्षा होगी। अगर उनके काम में संदेह हुआ तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बैठक भविष्य में की जाएगी।

दैनिक विश्वमित्र

कोलकाता, 9 अगस्त, 2011

19 August 2011



मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा आयोजित परिचर्चा सत्र को संबोधित करते हुए राज्य के सहकारिता व अंतर्देशीय जल परिवहन मंत्री हैदर अजीत सफवी। साथ में हैं चेम्बर के अध्यक्ष सुदेश कुमार सोंथलिया। विश्वमित्र

को-ऑपरेटिव आंदोलन को बढ़ावा देगा सहकारी विभाग : सफवी

कोलकाता, 9 अगस्त (निप्र)। राज्य में सहकारी आंदोलन को और भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से नयी राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र सहकारिता विभाग का गठन किया गया है। नव गठित इस विभाग द्वारा को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस शिकायत के आधार पर रद्द किया गया था। इसलिए राज्य के सहकारी विभाग ने जहां एक ओर को-ऑपरेटिव बैंकों के विकास में ध्यान दिया है वहीं दूसरी तरफ सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में कार्य शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए राज्य के सहकारिता तथा अंतर्देशीय जल परिवहन मंत्री हैदर अजीत सफवी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना, ताकि जरूरत मंद लोगों का इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक से ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर किसानों को लाभ मिलता है, लेकिन गत वाममोर्चा सरकार के कार्यकाल में इन बैंकों की आर्थिक दशा काफी खराब हो गयी है। इसलिए राज्य सरकार ने को-ऑपरेटिव बैंकों को सुधारने हेतु कार्य शुरू कर दिया है। मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा यहां आयोजित 'सहकारिता व अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु योजना' शीर्षक परिचर्चा सत्र में श्री सफवी ने कहा कि हाल ही में आरबीआई के अधिकारियों ने एक बैठक की थी। बैठक में को-ऑपरेटिव बैंकों की आर्थिक सुधार हेतु फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि हुगली जलपथ परिवहन समवाय समिति के कामकाज की जांच के लिए जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। श्री सफवी ने कहा कि सहकारी विभाग की ओर से पर्यटन उद्योग के विकास में सहयोग करेगा। फिलहाल विभाग को कई नये कार्य सौंपे गये हैं। इस अवसर पर चेम्बर के अध्यक्ष सुदेश कुमार सोंथलिया ने स्वागत भाषण दिया।

जनसत्ता, कोलकाता, 10 अगस्त 2011

जलपथ परिवहन को स्वतंत्र विभाग बनाया जा रहा है : सफवी

जनसत्ता संवाददाता

कोलकाता, 9 अगस्त। परिचय बंगाल के सहकारिता व जलपथ परिवहन मंत्री हैदर अजीत सफवी ने मंगलवार को कहा कि जल परिवहन विभाग को स्वतंत्र विभाग बनाया जा रहा है। पहले यह भूतल परिवहन निगम लिमिटेड के तहत था। वे मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कामर्स के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता संगठन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। उनके बोर्ड में सरकार का सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। नियुक्तियों से लेकर सारे वित्तीय फैसले वे खुद करते हैं। लाभ-हानि के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। करीब 30 प्रतिशत सहकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं। राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि उनकी स्थिति को सुधारे। उन्होंने सहकारिता और जलपथ परिवहन के क्षेत्र में निजी-सरकारी साझेदारी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) को प्रमुखता देने की बात कही।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि कई सहकारी बैंकों में भारी आर्थिक अनियमितताएं सामने आई हैं। इसी के कारण हावड़ा के एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करना पड़ा। कुछ सहकारी बैंकों

के बोर्ड को भंग करना पड़ा। इन बैंकों में अनियमितताएं हुई हैं। इन बैंकों के बोर्ड में वामपंथी लोगों को भर दिया गया है। वे अपने हित में काम कर रहे हैं। नतीजा यह है कि आम आदमी का हित नहीं हो रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में आलू की खरीददारी में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। आरोप था कि आलू खरीदा ही नहीं गया लेकिन उसे कागज पर खरीदा और बेचा गया। इसमें घाटा वगैरह दिखा कर रुपए रख लिए गए। अब इस तरह के घोटालों पर प्रतिबंध लग गया है। हम ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं।

नई सरकार के आने के पहले हुगली जलपथ परिवहन समवाय के कर्मचारियों का वेतन 40 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। जबकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी लांच सेवा काफी सस्ती है और इससे यात्रियों को काफी सुविधा है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके सामने कोई दिक्कत न आए।

मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। इससे राज्य के किसानों को लाभ पहुंचेगा।

Govt may hive off inland water transport system

Our Bureau

Kolkata, Aug. 9

The State Government may soon hive off inland water transport system into a separate department.

Inland water system is currently under the State Surface Transport Department, according to Mr Haider Aziz Safwi, Minister of Co-operation and Inland Water Transport, West Bengal.

"The work distribution is under way and it will be notified shortly. The inland water system has been under the surface transport system for the last few years. We are proposing a new department for it and it will start functioning shortly," he said,

while talking to newsmen on the sidelines of an interactive session organised by the Merchants' Chamber of Commerce here on Tuesday.

On being asked about the plight of sick co-operative banks in the State, he said, "We recently met the senior officials of Reserve Bank of India and they have asked us to submit a plan for the revival of the sick co-operative banks in the State and we are working on it."

There were close to 40 sick co-operative banks in the State.

"These banks need to be revived in order to protect the interest of depositors," he said.

प्रभात खबर

कोलकाता, बुधवार, 10 अगस्त, 2011

राज्य के मंत्री हैदर अजीज साफवी ने कहा फिशिंग ट्रॉलर से यात्रा पर लगेगी रोक

संवाददाता ■ कोलकाता

मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल में लाये जानेवाले ट्रॉलर को यातायात का माध्यम बना दिया गया है। इसमें लोग सफर कर रहे हैं। इस पर पाबंदी लगायी जायेगी। राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर है। यह कहना है राज्य के भू-गर्भ जल परिवहन व सहकारी मामलों के मंत्री हैदर अजीज साफवी ने कहीं। वह मंगलवार को मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य में फिशिंग ट्रॉलरों की संख्या का पता नहीं है। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। इसके लिए ट्रॉलरों का पंजीकरण कराया जा रहा है। साथ ही

जल परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नये तरह के लांच उतारे जायेंगे।

को-ऑपरेटिव पर नजर

मंत्री ने बताया कि सूचना मिली है कि राज्य के कई को-ऑपरेटिव सोसाइटी में कामकाज सही तरीके से नहीं चल रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही को-ऑपरेटिव सोसाइटी की सेवाओं का विस्तार किया जायेगा। इस विषय पर मंगलवार को एक बैठक हुई थी। इसमें उत्तर हावड़ा के विधायक अशोक घोष, हावड़ा की जिलाधिकारी संघमित्रा घोष, परिवहन विभाग के सचिव और को-ऑपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि मौजूद थे।

राज्य में फिशिंग ट्रॉलरों की संख्या की जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं

ट्रॉलरों का कराया जा रहा है पंजीकरण

जल परिवहन को और बेहतर बनाने की योजना बना रही है सरकार



मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से चेंबर सभागार में आयोजित परिचर्चा में राज्य के आंतरिक जलपथ परिवहन मंत्री हैदर अजीज साफवी एवं चेंबर अध्यक्ष सुदेश साँधलिया
(-चित्र: भारतमित्र)

भारतमित्र

कोलकाता, बुधवार, 10 अगस्त, 2011

सकालबेला • १० अगस्त, २०११

हृगलि नदी जलपथ परिवहण प्रशासक नियोग करवे राज्य

स्टाफ रिपोर्टर: हृगलि नदी जलपथ परिवहण समवाय समितिके बाँचाते आर्थिक दाय नेवे ना राजा सरकार। तबे सृष्टुभावे समवाय याते चले, तार जना प्रशासक नियोग करा हवे। मङ्गलवार 'समवाय एवं जलपथ परिवहण'-एर उपर आयोजित एक आलोचनासभाय एकथाई जानालेन राजेय समवाय एवं जलपथ परिवहणमन्त्री हायदार आजिज सफि। मार्चेस्टस चेखार अफ कर्मास आयोजित एही आलोचनासभाय तिनि जानान, 'विषयति निले एदिनई बैठक हयेछे। संस्थाति रूग्ण हउया सन्धेउ, दु'मास आगे कर्मीदेर बेतन बाड़ानो हयेछे। आय यथन बाड़छे ना तथन बेतन केन बाड़ानो हल? सरकार केनउ रकम आर्थिक प्याकेज देवे ना ओइ संस्थाके। तबे प्रशासक नियोग करा हवे।' जाना गियेछे, एही मिटिंगे समितिर कर्ताव्यक्तिदेर पाशापाशि उपस्थित छिलेन राजेय परिवहण दफतरेर सचिव, समवाय उ जलपथ परिवहण दफतरेर सचिव एवं दु'जन

विधायक। ये जेटीति ओइ संस्था व्यवहार करे, ता हृगलि नदी जलपथ परिवहण समवाय समिति संस्कार करे ना बलेउ फ्लेड उगरे देन तिनि। सरकारि



परिवहण संस्था झुतल परिवहणउ वे श्रुतिते चलाछे, एदिन ताउ जानान तिनि।

जलपथ परिवहण निले तार किछु परिकर्णनार कथाउ एदिन बलेन तिनि। तिनि बलेन, जलपथ

परिवहण एखन एकटि डायरेक्टेरेट। तबे शीघ्रई एटि एकटि आलादा पुर्णस डिपार्टमेन्ट हवे। तार परई विभिन्न परिकर्णना वास्तुवायित करा हवे। सुन्दरबन एलाकाय माछ धरार नौकोते यात्री बहनेर मते घटना प्रसङ्गे तिनि बलेन, यात्री बहनेर जना प्रतिटि माछ धरार नौकोकेई रेजिस्ट्रेशन करते हवे सरकारेर काछे। सरकार निरापत्ता विषयक सब दिक् खतिये देखेवे। नतून करे 'पिपिपि' मडेले जलपथ परिवहणके टेले साजानो हवे बलेउ तिनि मन्त्रव्य करेन।

समवाय प्रसङ्गे तिनि फ्लेड उगरे देन पूर्वतन सरकारेर उपर। तिनि बलेन, आगेर सरकार गत दु'बहरे एमन किछु सिद्धान्त निलेछिल, या जनसार्थवाही नय। विभिन्न जायगाय 'राजनैतिक नियोग' हयेछे। सरकारेर बदलेउ तारा बहल तबियेते रये गियेछेन सेइसब पदे। दुनीतिउ हयेछे नाना समवाये। एकाधिक समवाये दुनीतिर तदन्तउ शुरु हयेछे बले तिनि जानान।

গীতাঞ্জলি ষড়্‌ঈক্ষণ মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা উদ্‌ঘাটিত

কলকাতা, ৯।৮ (নি.প্র) - দক্ষিণ কলকাতাওরে কেবলমুখ্য
চম্বলু চব্বুকু প্রাচলৈল চাৰ্চনরযিচ
উদ্যমরে বহুপুণ্ডা পুৰ্বিখাযুক্ত
গীতাঞ্জলি ষড়্‌ঈক্ষণ আৰ্চি মুখ্যমন্ত্রা
মমতা বানার্জীকদ্বারা উদ্‌ঘাটিত
হোলয়ালিছ।

উদ্‌ঘাটন বরারে মেয়র
গোলন চচোচাখাছ বরোচতি
করিথবাবেকৈ চৌর ও নগর
উদ্যন মস্তা চৌরদ হাৰ্চি,
ক্লাভামস্তা মদন মিত্র, বিচর্যম
মুকাবেলা মস্তা জাভেদ অহম্মদ
গান, কাউনসিলর মুগাচ বোম্ব
চুপুগ বক্ৰব্য রঙিথলে।

রাজকাজা ষড়্‌ঈক্ষণওরে
আমোচিত এই উদ্‌ঘাটন
উত্ববরে মুখ্যমন্ত্রা মুগা বানার্জী
কহিথলে যে চরিবেগকু বুরষিচ
রঙিবা চাৰ্চি বজলি চাৰ্চি
আকগ্যকতা রহিছ। যেহিচরি
কর্ণকুচ জাবনরে বিগ্ৰাণ ও
মনোরজন চাৰ্চি মখ বংসুচি
কৈহিক আযর কবুর। কলকাতা
মহানগরাকু বিহিন্ বহিচ করিবা

চাৰ্চি চৌরযতা ও রাক্য বরকার
যেছ উদ্যম গুহগ করিছি চাছা
যচক রুচু নেনলে চুকুতরে
চুস্তাৰ্চি কলকাতা মহানগর
লঙনরে চরিগত হেব। এই
শেষরে চুচেযক আবেল আযিবা
ছচি। দক্ষিণ কলকাতার বজলি
বহুপুণ্ডা চাৰ্চি চুচিষা চাৰ্চি চাৰ্চি
খরি উদ্যম চাৰ্চিথলা, চাছাকি
চুরগ হেছি। নগর উদ্যন
মস্তা চৌরদ হাৰ্চি কহিথলে যে
মুখ্যমন্ত্রা লম্বকু বুকুচু
চুচু চাৰ্চি চুচেযককু বক্ৰ
নেককু হেব। আৰ্চিক বংক
মখরে কনযাচাৰ্চিক চাৰ্চি
বহুপুণ্ডা মুচোচ মুষি করোছ।
মেয়র গু চচোচাখাছ কহিথলে
যে এই ষড়্‌ঈক্ষণ চিমাগ চাৰ্চি
৭৪কোচি চকা বম্ব হোলিছ।
খওরে জাচাচ ও আচকাচ
মানর চুরবল, ক্ৰিকচ ও অচাচ
আছচচোর গেক হোলচাচি।
৪ছকার চৰ্চিক খওরে
কবিচরিবে। যেহিচরি কঙোর
গেচ মখ হোলচাচি।



খণবিবিআর বলা গুহরে চৰ্চিচবকর মস্তা ছাচকর অক্ৰিচ ঘাৰ্চি ও অখম্ব
বুবেক ঘাচুচিখ।
চচো : খণ/ক

এক নজর

জল পরিবহন में होगा सुधार : सफवी

कोलकाता : सरकार निजी संस्थाओं के साथ मिलकर जल परिवहन सेवा में सुधार करेगी। इसके लिए सरकार विस्तृत योजना बना रही है। यह बात आज मंचेंट चेंबर आफ कामर्स द्वारा आयोजित वार्ता सत्र में कोआपरेशन व इनलेड वाटर ट्रांसपोर्ट मंत्री हैदर अजीज सफवी ने कही। उन्होंने कहा कि अधिकतर जल परिवहन कोआपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा की जेटियों आदि को दुरुस्त करने की जरूरत है, जिसके लिए राज्य सरकार मुकम्मल योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि तत्काल योजनाओं का खुलासा नहीं किया जा सकता है लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर है।

SANGBAD PRATIDIN 10 AUGUST 2011



मङ्गलवार बणिक सभार एक अनुष्ठाने राजेयार समबायमन्त्री एहच ए सफिके
स्वागत जानाछेन बणिकसभार सभापति एस साहूलिया। —प्रतिदिन चित्र

জলপথ পরিবহনের বেহাল দশা সিপিএমকে দুশলেন সফি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপথ পরিবহনের বেহাল দশার জন্য
বিগত বাম সরকারকে দুশলেন রাজ্যের সমবায় ও
অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ মন্ত্রী। কলকাতা ও তার
পার্শ্ববর্তী এলাকায় জল পথে পরিবহণের জন্য ২১টি জেটি
তৈরি হবে। এর জন্য আগেই ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
তবে জেটিগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে সংশ্লিষ্ট
সংস্থাকেই।

মঙ্গলবার মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সে এক সাংবাদিক বৈঠকে
এই কথা জানান রাজ্যের সমবায় ও অভ্যন্তরীণ জলপথ
পরিবহণ মন্ত্রী হায়দার আজিজ সফি। তিনি অভিযোগ

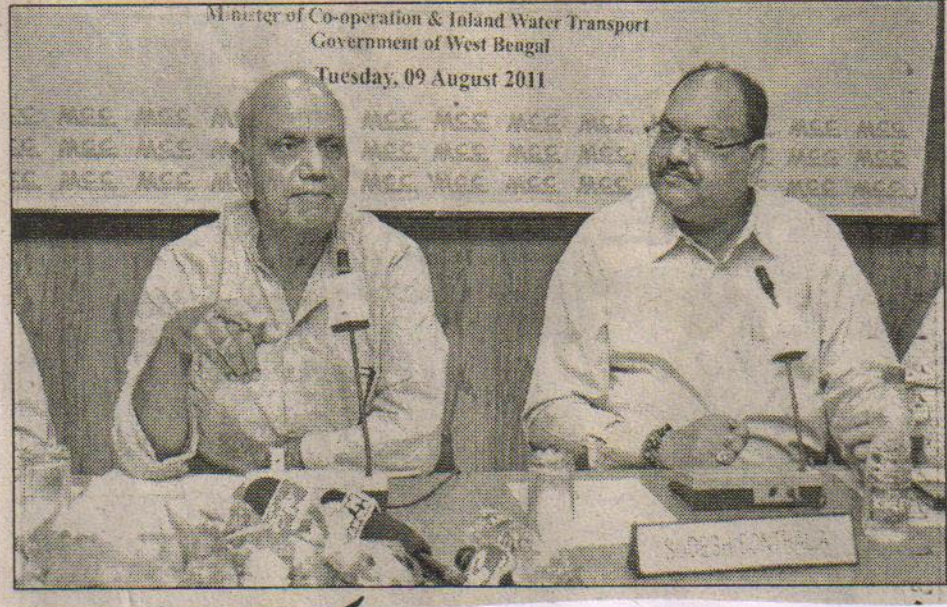
করেন, আগের সরকারের আমলে সিপিএমের দৌলতে
হুগলি জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতিতে কর্মীদের বেতন
বেড়েছে ৪০ শতাংশ অথচ সেই তুলনায় আয় বাড়েনি। এই
ধরনের সংস্থার আয় বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আলু চাষিরা যাতে সঠিক দাম পায়,
হিমঘরে আলু সংরক্ষণ করতে পারে সেই বিষয়টিও দেখা
হবে। বিধানসভায় অধিবেশন চলার জন্য ভবিষ্যৎ
পরিকল্পনার কথা এ দিন তিনি বলতে চাননি।

তবে তিনি বলেন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির হাল ফেরানোর
চেষ্টা করা হবে।

Minister of Co-operation & Inland Water Transport
Government of West Bengal

Tuesday, 09 August 2011



DURANTA BARTA

11 August 2011, Thursday

রাজ্য জলপথে যাত্রী পরিষেবার প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গে আন্তঃরাজ্য জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুন্দরভাবে গড়ে তোলার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। আর এই সুযোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যে গত মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, গত বার জামানায় আন্তঃরাজ্য জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেই অর্থে উন্নতি করা হয়নি। কারণ কোষাগারে ঘাটতি। বর্তমানে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করেছে। এরজন্য খরচ করা হবে দুটি খাতে সেন্ট্রাল স্পন্দরড স্কীমে এবং ইংল্যান্ড ভেসেল বিল্ডিং সার্ভিসেস স্কীমে। পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন সংস্থার দ্বারা ভূটভূটি ও বাস পরিষেবা চালু আছে। ফেরি চলাচলের জন্য ১৫ টি জেটি এবং বাস পরিবহনের জন্য একটি ডিপো আছে। ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস আরও উন্নতির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিবেণী ও ফারাক্কার

মধ্যে 'ন্যাশানাল ওয়াটার ওয়ে ১' তে জেটি গুলির সংস্কার করা হবে। মোট ৮৮ টি স্কীম চুক্তি বন্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে ৩০টি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনার জন্য খরচ বহন করছে ৯০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকার এই খাতে খরচ করছে ১০ শতাংশ। এদিন শ্রী হায়দার আজিজ সোফি বলেন, জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির প্রচুর সুযোগ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বাগবাজার-কেম্পুর ফেরি ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েকমাস চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি জানান, এই সব বন্ধ হয়ে যাওয়া ফেরি ব্যবস্থা গুলি পুনরায় চালু করা যেতে পারে। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যদি জল পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে তাহলে তা পর্যটন শিল্পেরও প্রসার ঘটাবে। এ ব্যাপারে ইন্টার ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।